भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2151
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

शैक्षणिक अवसंरचना में सुधार

†2151. श्री सालेंग ए. संगमा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है;
(ख) यदि हां, तो इस मिशन के अंतर्गत शिक्षकों को प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों और संसाधनों का ब्यौरा क्या है**;**
(ग) सरकार द्वारा विशेषकर ग्रामीण और अल्पसुविधा प्राप्त क्षेत्रों और विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में शैक्षणिक अवसंरचना में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) बच्चों में सीखने के परिणामों में सुधार लाने के संबंध में ऐसी पहलों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): शिक्षकों को सीखने के निरंतर अवसर प्रदान करने के लिए, अक्टूबर 2020 में दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना) प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) ऑनलाइन शुरू की गई ताकि प्राथमिक शिक्षकों तक पहुंच बनाई जा सके और इसे सभी स्तर के शिक्षकों तक आगे बढ़ाया जा

सके। इसमें बातचीत के लिए कई दृष्टिकोण जैसे कि वीडियो के साथ-साथ टेक्स्ट मॉड्यूल शामिल हैं। ये सभी सामग्रियां मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान (एफएलएन) के विकासात्मक लक्ष्यों और अधिगम परिणामों के अनुरूप हैं।

आंगनवाड़ियों में उच्च गुणवत्ता वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) शिक्षकों का एक प्रारंभिक संवर्ग तैयार करने के लिए, जुलाई, 2022 में निष्ठा-ईसीसीई और एफएलएन शुरु किए गए थे। इसका उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास के लिए विकासात्मक रूप से उपयुक्त शिक्षाशास्त्र पर मास्टर प्रशिक्षकों को जागरूक बनाना है जो आधारभूत स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने में योगदान देगा। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रीस्कूल शिक्षकों दोनों के प्रशिक्षण को पूरा करते हैं।

(ग): समग्र शिक्षा योजना सरकारी स्कूलों में छात्रों के लिए बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के निर्माण में सहायता करती है। इस संबंध में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं और प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) तैयार किया जाता है। इन योजनाओं का मूल्यांकन/अनुमोदन परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम संबंधी और वित्तीय मानदंडों तथा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। सरकार द्वारा विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत पृथक शौचालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, आईसीटी प्रयोगशाला, स्मार्ट कक्षा आदि की व्यवस्था की जा रही है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को 90:10 के अनुपात में धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, जबकि अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वित्तपोषण मानदंड 60:40 है।

(घ): बच्चों की प्रगति और अधिगम क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल), शिक्षा मंत्रालय तीन वर्ष के अंतराल के साथ तीसरी, पांचवीं, आठवीं और दसवीं कक्षा के लिए नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का एक कार्यक्रम कार्यांवित कर रहा है। यह शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में कार्य करता है, ताकि विभिन्न स्तरों पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 720 जिलों के 1.18 लाख स्कूलों के लगभग 34 लाख छात्रों का सरकारी और निजी स्कूलों से मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा, प्रत्येक प्रकार के स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने वाले एनएएस 21 के राष्ट्रीय, राज्य और जिला रिपोर्ट कार्ड दिनांक 25.05.2022 को http://nas.gov.in पर सार्वजनिक डोमेन में जारी किए गए हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के अंतर्गत डीओएसईएंडएल द्वारा परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना की गई है। इसने राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण (एसईएएस) 2023 आयोजित किया है। इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक शैक्षिक चरण अर्थात् आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य स्तर के अंत में आधारभूत साक्षरता, आधारभूत संख्याज्ञान, भाषा और गणित में छात्रों की अधिगम क्षमताओं का मूल्यांकन करना है। एसईएएस-23 ने ब्लॉक स्तर पर सीखने की कमियों को समझने के लिए छात्रों को कवर करने के लिए नमूने में ब्लॉकों को शामिल किया है, जो जिले से एक रणनीतिक बदलाव है। एसईएएस-23 में 6416 शैक्षणिक ब्लॉकों के 4 लाख स्कूलों के लगभग 8.4 मिलियन छात्रों और 6 लाख शिक्षकों का मूल्यांकन किया गया।

*****